

जिले में नवचयनित आठ प्रवक्ताओं एवं 135 सहायक अध्यापकों को दिया गया नियुक्ति पत्र

अफीम कोठी सभागार में हुआ कार्यक्रम

प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुगार को लखनऊ में नवचयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण आज जिसका सीजीव प्रसारण आज क्षेत्रीय प्राप्ति विकास संस्थान अफीम कोठी के सभागार में विद्यायक विश्वनाथगंग डा० आर००के वर्मी, विद्यायक रामेश धीरज औजा, जिला लाइकारी डा० नितिन बंल, मंती मंती सिंह के प्रतिनिधि निनद पाण्ड्य, मंती महेन्द्र सिंह के प्रतिनिधि दिवेश शर्मा, विद्यायक सदर के प्रतिनिधि अशोक पाल, अफीम कोठी के प्राचार्य शिव प्रकाश, जिला विद्यालय निरीक्षक सर्वदानन्द



सिंह सहित अन्य नवचयनित आठ प्रवक्ताओं एवं 135 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण विद्यायक, जिलालाइकारी व अन्य नवचयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक

इसी क्रम में जनपद के

अध्यापकों को बधाई देते हुये कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाकर योग्य लोगों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गयी है। इस दौरान विद्यायक धीरज औजा ने नवचयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को शुभकामनाएं देते हुये किंवदं का विद्यायक है कि वे अपनी क्षमता का उत्तरोग्य छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने में लगाएं। कार्यक्रम में जिलालाइकारी डा० नितिन बंल ने सभी नवचयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक अध्यापकों को बधाई देते हुये कहा कि वे अपनी क्षमता का उत्तरोग्य छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने में लगाएं। कार्यक्रम का संचालन मात्र अनीस द्वारा किया गया।

क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान के सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम के दौरान विद्यायक डा० आर००के वर्मी ने नवचयनित प्रवक्ताओं एवं सहायक

एवं सहायक

अष्टभुजा इंटर कालेज में लगे नेत्र शिविर में 167 रोगियों का हुआ परीक्षण आपरेशन के लिये 42 लोगों को भेजा गया चित्रकूट

प्रतापगढ़। एक दृस्त के तत्वावधान में अष्टभुजा इंटर कॉलेज जेठवारा में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 167 रोगियों का परीक्षण किया गया और 42 को आपरेशन हुत भेजा गया। शुभारंभ एस०ओ००ठेठवारा ने किया। इस दौरान उन्होंने अपने विभाग के लोगों की भी नेत्र परीक्षण कराया। प्रथानानायार्य लाला प्रसाद पाण्ड्ये के संयोजन में आयोजित इस नेत्र शिविर में डॉ० शिवाकांत विपाणी एवं डॉ० पंकज गृहन ने रोगियों का नेत्र परीक्षण किया। 167 रोगियों का युग्म नेत्र परीक्षण किया गया। 42 रोगियों को अपेक्षण हुत चिह्नित करके उन्हें बस द्वारा चित्रकूट भेजा गया जहाँ उनका मृत्यु अपरेशन कर्यालय पर व्याक स्तर पर सुधार लाएं। कार्यक्रम का संचालन मात्र अनीस द्वारा किया गया।

कहा कि इस शिविर का आयोजन अपरेशन करवाने में उन्हें सफलता मिल रही है। शिविर वें व्यवस्थापक अनंत सिंह तोमर ने भविष्य में भी ऐसे शिविरों के आयोजन की बात कही। इस अपरेशन करवाना का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही कमज़ोर एवं तोमर, राम सिंह प्रद्यान, राजेश गरीबों का मुक्त इलाज हवे सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

विद्यायक ने पीआरडी जवान को दी 21 हजार की मदद

प्रतापगढ़। बदमाशों की गोली से घायल होकर जिंदी से जंग लड़ रहे पीआरडी जवान की मदद के लिये रानींग विद्यायक धीरज आगे आ रहे हैं। उन्होंने परिवार की आर्थिक दशा कमज़ोर होने के चलते उसके उपचार में आ रही परेशानी के लिये मदद की पहल की है। उन्होंने पीड़ित परिवार को इलाज के लिये 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी है। बता दें कि 22 जलाई को दिलीपपुर में पिकेट की ड्यूटी के दौरान बदमाशों की गोली से पीआरडी जवान पवन तिवारी घायल हुए थे। उनके उपचार में पैसे की परेशानी आ रही थी।

फिल्म कलाकार सज्जन सिंह के अस्थि कलश पर विद्यायक व नेताओं ने चढ़ाए पुष्प

प्रयागराज में गंगा में प्रवाहित हुई अस्थियां

प्रतापगढ़। सिनेमा कलाकार अनुपम श्याम औजा जो फिल्म अनुपम श्याम जेझा जो फिल्म अनुपम श्याम सेज्जन सिंह के नाम से जाने जाते थे, उनकी अस्थियां आज गुरुगार को प्रयागराज में गंगा में विसर्जित कर दी गई। इसके पहले बृद्धवर की शाम मुख्वाई से अनुपम श्याम के छोटे भाई आलोक श्याम औजा (कंचन) व अनुराग श्याम औजा (रतन) अस्थि कलश लेकर टेढ़न से प्रतापगढ़ पहुंचे।

गुरुगार का प्रातः अनुपम श्याम का अस्थि कलश स्टेशन रोड स्थित उत्के आवास पर रखा गया था जहाँ विद्यायक विनोद सरोज, पूर्व विद्यायक बृजेश सरारथ, काण्पेश के जिलालाइक लालजी के सुखारी भाई विनोद के द्वाहशत फैल गई। जबकि आरोपी फैजयज व आसिफ निवासी पूर्वे पाण्ड्ये कम्हीरा तथा मुरुजा ने चुट्टिल पर जानलेवा फायरिंग कर उसे लहूलुहान कर दिया। फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। जबकि आरोपी सुरेंद्र सिंह ने गंगा के रामासरे व रामअंजोरों की साजिश पर घटना को लेकर आपाराधिक घटयंत्र किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी रुद्रिका के खिलाफ हत्या के प्रयास सेमेत को खिलाफ विद्यायक व नेताओं ने जय राम बनवासी को भी जिलालाइक बनाया गया। इस पर भाजपा जिलालाइक हरि ओम मिश्र सहित जिला कार्यकारियों के पदाधिकारी व नेताओं ने जय राम बनवासी को मनोनयन पर बधाई दी है।



ओजा, जनसत्ता दल वें जिलालाइक रामअंचल वर्मी, जिला पंचायत अध्यक्ष रामाचल वर्मी, जिला जनसत्ता सेज्जन सिंह के नाम से जाने जाते थे, उनकी अस्थियां आज गुरुगार को प्रयागराज में गंगा में विसर्जित कर दी गई। इसके पहले बृद्धवर की शाम मुख्वाई से अनुपम श्याम के छोटे भाई आलोक श्याम औजा (कंचन) व अनुराग श्याम औजा (रतन) अस्थि कलश लेकर टेढ़न से प्रतापगढ़ पहुंचे।

उनका अस्थि कलश बृद्धवर की शाम साढ़े सात बजे टेढ़न द्वारा प्रतापगढ़ लाया गया। बृद्धवर को दिन में लगभग बार बजे अनुपम श्याम का अस्थि कलश पर पुष्प दबाए। बता दें कि 22 जलाई को दिलीपपुर में पिकेट की ड्यूटी के दौरान बदमाशों की गोली से पीआरडी जवान पवन तिवारी की विद्यायक व नेताओं की अस्थियां विसर्जित किया गया।

भारी बारिश के कारण घर पर गिरा नीम का पेड़, मकान क्षतिग्रस्त सई नदी का पानी अभी खतरे के निशान से नीचे, प्रशासन सतर्क

प्रतापगढ़। गुरुगार को भी दोपहर तक वर्षा की बारी रही रहा। दोपहर बाद पानी रुका है, तब लग बाहर निकल पाए हैं। वर्षा तक रात से ही हो रही थी। सबह उठने पर पानी का क्रम जारी रहा। जिला अस्पताल में जलभरात का संकट दूसरे दिन भी बारा रहा। शर्म से जायरात वर्षा के साथ आयी थी। अल्ला, लोक गीत, कजरी आदि का गायन की भी बढ़ावा दिया जाता रहा। साथ ही दो की तरह दोहरा प्रतिवर्षित में प्रयागराज प्रतिवर्षित में जलभरात का गायन आया। अल्ला, लोक गीत, कजरी आदि का गायन की भी बढ़ावा दिया जाता रहा।



रुकने से कल से एवं अधिकतम तापमान कुछ बढ़ा है। आज दूसराम तापमान 24.5 व अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री रिकार्ड किया गया। नगर को तापमान 29.2 डिग्री रिकार्ड किया गया। नगर को तापमान 29.2 डिग्री रिकार्ड किया गया। जिला अस्पताल में जलभरात का गायन आया। अल्ला, लोक गीत, कजरी आदि का गायन की भी बढ़ावा दिया जाता रहा।

पीड़ित मकान मालकिन अरवन देवी पतनी को लाली प्रसाद मिश्र को पहले से भी अनहोनी की ओंकार हो चुकी थी कि किसी ना किसी दिन पेड़ पर गिर जाएगा और बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस संबंध में पीड़ित ने जिलालाइकरी प्रतापगढ़ को कुछ दिन पूर्व प्रार्थना पत्र दिया था। नीम का पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया।

पीड़ित मकान मालकिन अरवन देवी पतनी को लाली प्रसाद मिश्र को पहले से यही कि किसी ना किसी दिन पेड़ पर गिर जाएगा और बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इस संबंध में पीड़ित ने जिलालाइकरी प्रतापगढ़ को कुछ दिन पूर्व प्रार्थना पत्र दिया था। नीम का पेड़ गिरने की है।

विद्यायक डा० वर्मा के बयान पर राष्ट्रीय परशुराम सेना ने जाताया विरोद्ध

प्रतापगढ़। जिले में दिनों सुधियों बढ़ावरने के लिए नेता से लेकर धर्म जाति आधारित संगठन बेलगाम बायानपाता करने से बाज़ी आ रहे हैं। भारी विद्यायक जिला पार्टी के समर्थन से अपना दल के विश्वनाथगंग विद्यायक डा० आर००के वर्मी को जिलालाइक रामअंचल वर्मी, जिला संगठन अध्यक्ष रामाचल वर्मी लेकर शाम पहुंचा यहाँ आया। जिला जनसत्ता दल वें जिलालाइक रामाचल वर्मी और जिला जनसत्ता सेज्जन सिंह के नाम से जाने जाते थे, उनकी अस्थियां आज गुरुगार को प्रयागराज में गंगा में विसर्जित कर दी गई। इसके लिए नेतृत्व में जिला जनसत्ता दल के शीर्ष नेतृत्व से यह मांग करी गई है। जिला जनसत्ता दल के वर्षी न

सम्पादकीय

ओबीसी बिल के संकेत

कोई भी पार्टी इस गेट बैंक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह संदेश नहीं जाने देना चाहती कि वह उसके हितों की चिंता करने के मामले में औरों से पीछे है। यही वजह है कि केंद्र सरकार फटाफट बिल ले आई और विपक्ष ने भी पेगासस से लेकर कृषि कानूनों तक पर चल रही अपनी आरपार की लड़ाई को कुछ समय के लिए भुला देने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। लोकसभा ने ओबीसी लिस्ट बनाने के राज्यों के अधिकार से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को जिस तरह से पारित किया एवं वह काफी कुछ कहता है। पूरे मॉनसून सत्र के दौरान देखा गया विपक्ष का हंगामाए शोर शराबा और विरोध कुछ समय के लिए थम गया। इस बिल की खातिर विपक्ष ने अपना विरोध स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की असाधारण एकजुटता के बीच यह संशोधन विधेयक 385 बनाम शून्य मतों से पारित हो गया।

अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाना है और पूरी संभावना है कि वहां भी यह ऐसी ही आसानी से पारित हो जाएगा। इस बिल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि स्थ्रीम कोर्ट ने 5 मई को दिए अपने एक फैसले में कहा कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों की अपनी सूची तैयार करने का अधिकार नहीं है। यानी राज्य सरकारें अपने स्तर पर किसी खास समुदाय को आरक्षण के दायरे में नहीं ला सकती।

यह अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। स्वाभाविक रूप से राज्य सरकारों ने इसे अपने अधिकारों में कटौती के रूप में लिया और विपक्षी दल केंद्र पर निशाना साथने लगे। मगर इस संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो रजामंदी दिख रही है उसके पीछे संविधान के संघातमक ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपों से ज्यादा ओबीसी समुदायों के मजबूत गोट बैंक की भूमिका है। कोई भी पार्टी इस गोट बैंक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यह संदेश नहीं जाने देना चाहती कि वह उसके हितों की चिंता करने के मामले में औरों से पीछे है। यही वजह है कि केंद्र सरकार फटाफट बिल ले आई और विपक्ष ने भी पेगासस से लेकर कृषि कानूनों तक पर चल रही अपनी आरपार की लड़ाई को कुछ समय के लिए भुला देने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। बिल पर सदन में हुई बहस में भी जो दो मुद्दे प्रमुखता से उठे वे थे। जाति आधारित जनगणना और आरक्षण पर लगी अधिकतम 50 फीसदी की सीमा को समाप्त करने की जरूरत। दोनों ही मसलों पर सरकार का सकारात्मक रुख रहा। 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण के संबंध में हालांकि उसने कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए सावधानी की जरूरत बताई लेकिन यह कहना नहीं भूली कि वह इस मसले पर सांसदों की भावना समझती है। जातिवार जनगणना को लेकर भी संकेत है कि 2021 में नियमित जनगणना का काम पूरा होने के बाद इसका काम शुरू करवाया जा सकता है। संसदीय राजनीति के सभी धड़ों में ऐसी व्यापक सहमति बताती है कि बहुत संभव है कि हम जल्दी ही एक बार फिर देश में आरक्षण को सभी रोगों की दवा बताने वाली राजनीति हावी होते देखें। एक समाज के रूप में इस दौर का भी सर्वश्रेष्ठ हमें मिलें इसके लिए राजनीति को थोड़ा और क्रिएटिव थोड़ा और कल्पनाशील बनना होगा।

ହର୍ଷବର୍ଧନ ଶ୍ରୁଂଗଲା

ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। यह भी पहली बार हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समुद्री सुरक्षा की कार्य सूची मद के तहत समुद्री सुरक्षा मामले पर चर्चा की गई। लालंकिए परिषद ने इससे पहले भी जल दस्तुता और सशस्त्र लूट से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है और अंततः भारत द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर परिषद ने सभी 15 सदस्य राष्ट्रों की सर्वसम्मति से समुद्री सुरक्षा संबंधी अध्यक्षीय वक्तव्य पारित किया। जो इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ऐसा पहला परिणामी दस्तावेज़ है। यूएनएससी अध्यक्षीय वक्तव्य में पुनःपुष्टि की गई कि महासागर कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में परिलक्षित अंतरराष्ट्रीय कानून में महासागरीय प्रयासों पर लागू विधिक ढांचा निर्धारित किया गया है। इसमें 26x11 मुंबई आतंकी हमले की तरह आतंकवादियों द्वारा समुद्र के उपयोग पर ध्यान आकर्षित किया गया है और ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए क्षमता निर्माण तथा प्रभावी प्रक्रियाओं को साझा करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा ए समुद्र में अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की निरंतर समस्या पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें महासागर के वैध उपयोग ए नाविकों एवं तटीय समुदायों के जीवन और आजीविका के सुरक्षा उपायों पर भी बल दिया गया है। इस कार्यक्रम में यूएनएससी के सदस्य राष्ट्रों से उच्च स्तरीय भागीदारी हुई है जिसमें चार राष्ट्रीयक्षात्सनाध्यक्ष और 10 मंत्री उपस्थित थे। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय शांति और दावों पर्याप्ती की परिकल्पना को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। करन वाल देश के रूप में अपना पहचान बनाइ हए जिसम मानवाय

सत्ता का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज

प्रखर वात्स्यायन

24 अप्रैल को देशभर में प्राचीर्य पंचायत राज्य दिवस मनाया जाता है। सत्ता में भागेदारी बनाने के मकसद से पंचायती राज का स्थापना हुआ था। 1993 में संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती व्यवस्था का परिणाम काफी बेहतर तो नहीं मगर आशा जनक रहा है। पंचायती राज के स्थापना होने से पिछड़े और वंचित लोगों को सशक्त बनने में मदद मिली है। हालांकि पंचायती राज का गठन 1950 में ही हो गया था मगर 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। महिलाएं आदिवासी और दलित को मिल रहे आरक्षण ने इस व्यवस्था को सशक्त तो बना दिया है। मगर सवाल यह है कि इससे सत्ता का विकंट्रीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या सच में समाज के हर वर्ग को सत्ता में प्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त हुआ है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलने का मकसद शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर के पंचायत और गाँव को मजबूत करना था। केन्द्र और राज्य सरकार शक्तियों को कम कर के स्थानीय राज को अधिकार देना का मकसद था। लोकतंत्र को पंचायत के स्तर पर मजबूत करना था। यह व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश तो कर रही है मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक उसी प्रकार से पंचायती राज का भी सफलता से लाभ नहीं है। ऐसे लैसे संवैधिती और संवैधानिक सम्बन्ध

भी नाकरात्मक प्रभाव भी है। लोग पैसे दबगागरा और नशोली पदार्थी फाइलें दबो रहे जाते हैं और उनको लाभ मिलने में काफ़ी समय का

क्या बहुमत पर भारी पड़ गया है अल्पमत ? हंगामे को देखते रहने के लिए क्यों मजबूर है सरकार ?

नीरज कुमार दुबे

देखा जाये तो यह संसद का नियमित सत्र जरूर था लेकिन इसके लिए तैयारियां विशेष रूप से की गयी थीं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए सत्र का आयोजन किया गया था। संसद परिसर में तमाम तरह के उपकरण लगाये गये थे ताकि किसी प्रकार के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। कोरोना की दूसरी लहर से जब देश जूझ रहा था और व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही थीं तब विपक्ष सरकार से बार-बार माँग कर रहा था कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाये ताकि महामारी से निपटने के उपायों पर चर्चा की जा सके लेकिन जब संसद के नियमित मौनसून सत्र का आयोजन हुआ तो उसे विपक्षी दलों ने चलने नहीं दिया। जब हर क्षेत्र में 100 प्रतिशत कार्य पूरा करने पर जोर दिया जाता है तो ऐसे में यह निराशाजनक ही है कि हमारे देश की संसद के निचले सदन लोकसभा में 22 प्रतिशत और ऊपरी सदन राज्यसभा में 28 प्रतिशत कामकाज ही हो पाया। देखा जाये तो यह संसद का नियमित सत्र जरूर था लेकिन इसके लिए तैयारियां विशेष रूप से की गयी थीं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए सत्र का आयोजन किया गया था। संसद परिसर में तमाम तरह के उपकरण लगाये गये थे ताकि किसी भी प्रकार के संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके। यही नहीं सत्र से पहले भारत-चीन तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ बैठकें कर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने उन्हें यथास्थिति की जानकारी दी थी। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और प्रधानमंत्री ने दूसरी मोदी की सर्वदलीय बैठकों में भी सभी दलों को यह आश्वासन मिला

ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि विपक्ष तीखे से तीखे सवाल पूछे मगर सरकार को जवाब देने का समय भी दे लेकिन विपक्ष तो जैसे पहले से ही ठानकर बैठा था कि किसी कीमत पर संसद को काम नहीं करने दिया जायेगा और वह अपने आभियान में सफल भी रहा।

हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, इन वर्षों में हमारे देश ने तरकी भी बहुत की है, हम दुनिया में लोकतंत्र की जननी हैं लेकिन दुर्भाग्य देखिये कि लोकतंत्र को इतना शर्मसार कर दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति सदन में रो पड़ते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं कि सदन में जो कुछ हुआ उससे मुझे बड़ी वेदना हुई। यह सब क्या दर्शाता है? क्या हमारा लोकतंत्र इतना मजबूर हो गया है कि बहुमत पर अल्पमत भारी पड़ रहा है? क्या विपक्ष इतना ताकतवर हो गया है कि देश के विकास की राह में बाधा उत्पन्न कर सके और सरकार सिर्फ देखती रहने को मजबूर हो? राज्यसभा में कभी मंत्रियों के हाथ से कागज छीनकर फाड़ गये, कभी सदन के नेता और मंत्रियों का घेराव किया गया तो कभी रिपोर्टर मेज पर चढ़कर नियमावली को आसन की ओर उछाला गया। क्या इसी तरह से लोकतंत्र चलता है?

किसान नेताओं के समर्थन में संसद के मौनसून सत्र का पूरा समय तो विपक्ष ने बर्बाद किया ही साथ ही इस सप्ताह मंगलवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने जो हरकत की उसने लोकतंत्र के सर्वीच मंदिर को शर्मसार कर दिया। पूरे देश ने देखा कि जिन सांसदों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी है उनमें से कुछ ने कैसे नियमों की धज्जियाँ उड़ाईं। ना सिर्फ दोनों सदनों की मर्यादा भंग की गयी बल्कि संसद के प्रति अविश्वास का भाव पैदा करने का प्रयास भी किया गया

क्योंकि आज के युग में यह जो पालूक है वह अच्छा तरह जनता है कि संसद की कार्यवाही के संचालन में हर घंटे लाखों रुपये खर्च होते हैं और इस खर्च की भरपाई जनता अपनी गाढ़ी कर्माई से करती है। बहरहाल, अब समय आ गया है कि सदन की कार्यवाही के संचालन से जुड़े नियमों को और सख्त बनाया जाये साथ ही नो वर्क नो पे का सिद्धांत हमारे माननीयों पर भी लागू हो। जो लोग सत्र की बर्बादी को अपनी विजय मान रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि इसका गलत संदेश जनता के बीच गया है। देखा जाये तो सरकार और विपक्ष का तो फायदा हो गया लेकिन जनता ठगी गयी है। सरकार ने हंगामे के बीच अपना विधायी कामकाज निबटा लिया, विपक्ष ने हंगामा करके मीडिया की सुखियों में स्थान पा लिया। लेकिन जनता का क्या हुआ? वह तो ठगी गयी है क्योंकि जनता संसद में अपने मुद्दों से जुड़े विषयों पर चर्चा चाहती थी, जनता चाहती थी विपक्ष सरकार से जवाब मांगे, जनता चाहती थी कि सरकार जिन विधेयकों को पारित करा रही है उनसे संबंधित सभी पहलू चर्चा के दौरान उसको अच्छी तरह से समझ आएँ। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। यही नहीं यह भी पहली बार हुआ जब संसद में देश के प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं रख पाये। खैर... कहा जा सकता है कि जिन नेताओं को खुशफहमी पालनी है कि उन्होंने संसद का समय और जनता के पैसे की बर्बादी कर बहुत अच्छा काम कर दिया है वह खुशफहमी पाल सकते हैं, यदि वह आप जन के बीच जाकर पता लगाएं तो ज्ञात होगा कि यही भावना प्रबल हो रही है कि विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया है। इस समय सदन में आचरण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जिस तरह का आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है वह आगामी दिनों में और बढ़ने की संभावना भी स्पष्ट नजर आ रही है।

रामप्पा मंदिर के जरिये भारत की सनातन संस्कृति की चमक फिर विश्व भर में फैली

डॉ. नीलम महेंद्र

रामपा मंदिर का विश्व धरोहर बनने का सफर 800 साल लंबा है जो शुरू हुआ था 1213 में जब तेलंगाना के तत्कालीन काकतीय वंश के राजा गणपति देव के मन में एक ऐसा शिव मंदिर बनाने की प्रेरणा जागी जो सालों साल उनकी भक्ति का प्रतीक बनकर मजबूती के साथ खड़ा रहे। भारत ने एक बार फिर विश्व को अपनी ओर आकर्षित ही नहीं किया बल्कि अपनी संस्कृति और कला का लोहा भी मनवाया। तेलंगाना के रामपा मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जाना एक तरफ भारत के लिए गौरव का पल था तो विश्व के वैज्ञानिकों के लिए एक अचंभा भी था। दरअसल आज से लगभग 800 साल पहले निर्मित रामपा मंदिर सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर ही नहीं है बल्कि ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण भारत के गौरवशाली अतीत का जीवित प्रमाण भी है। यह पत्थरों पर उकेरा हुआ एक महाकाव्य है। वो महाकाव्य जो 800 सालों से लगातार शान से भारत की वास्तुकला और विज्ञान की गाथा गा रहा है। और अब तो इसके सुर विश्व के कोने-कोने को मुग्ध कर रहे हैं। रामपा मंदिर का एक मंदिर से विश्व धरोहर बनने का यह सफर लगभग 800 साल लंबा है जो शुरू हुआ था 1213 में जब तेलंगाना के तत्कालीन काकतीय वंश के राजा गणपति देव के मन में एक ऐसा शिव मंदिर बनाने की प्रेरणा जागी जो सालों साल उनकी भक्ति का प्रतीक बनकर मजबूती के साथ खड़ा रहे। यह जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी वास्तुकार रामपा को। और रामपा ने भी अपने राजा को निराश नहीं किया। उन्होंने अपने राजा की इच्छा को ऐसे साकार किया कि राजा को ही मोहित कर लिया। इतना मोहित कि उन्होंने मंदिर का नामकरण रामपा के

ही नाम से कर दिया। आखिर राजा मोहित होते भी क्यों नहीं, रामपा ने राजा के भावों को बेजान पत्थरों पर उकेर कर उह्हें 40 सालों की मेहनत से उसे एक सुमधुर गीत जो बना दिया था। जी हाँ, रामपा ने 40 सालों में जो बनाया था वो केवल मंदिर नहीं था, वो विज्ञान का सार था तो कला का भंडार था। यह कलाकृति एक शिव मंदिर है जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किसी शिल्पकार के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि उसके द्वारा बनाया गया मंदिर उसके नाम से जाना जाए। आज भी यह विश्व का शायद इकलौता मंदिर है जो अपने वास्तुकार के नाम पर जाना जाता है। मशहूर खोजकर्ता मार्की पोले ने जब इसे देखा था तो इसे ठमंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला सिताराठ कहा था। दअरसल जब इस मंदिर का अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों और पुराततेलों और के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि इसका कला पक्ष भारी है या इसका तकनीकी पक्ष। सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि यह चमत्कार है या विज्ञान की, 17वीं सदी में जब इस इलाके में 7.7 से 8.2 रेक्टर का भीषण भूकंप आया था जिसके कारण इस मंदिर के आसपास की लगभग सभी इमारतें ध्वस्त हो गई थीं, लेकिन 800 साल पुराना यह मंदिर ज्यों का त्यों बिना नुकसान के कैसे खड़ा रहा? इस रहस्य को जानने के लिए मंदिर से एक पत्थर के टुकड़े को काट कर जब उसकी जाँच की गई तो पत्थर की यह विशेषता सामने आई कि वो पानी में तैरता है! राम सेतु के अलावा पूरे विश्व में आजतक कहीं ऐसे पत्थर नहीं पाए गए हैं जो पानी में तैरते हों। यह अभी भी रहस्य है कि ये पत्थर कहाँ से आए क्या रामपा ने स्वयं इहें बनाया था? आज से 800 साल पहले रामपा के पास वो कौन-सी तकनीक थी जो हमारे लिए 21वीं सदी में भी अजूबा है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर को उसका यह स्वरूप देने से पहले रामपा ने ऐसा ही एक

सहायता और आपदा राहत के लिए सबसे पहले कार्गाई करना भी शामिल है। पश्चिमी बिंदु मद्रासागर में अपने पड़ीसियों से पापृत द्वाल के अन्तर्गत हैं।

सहायता और आपदा राहत के लिए सबसे फहले कार्रवाई करना भी शामिल है। पश्चिमी हिंद महासागर में अपने पड़ोसियों से प्राप्त हाल के अनुरोधों पर भारत की तरित कार्रवाई ए सागर और घसुर्धी बूटुम्बकमण्ड दोनों के संबंध में प्रथान मंत्री के विजन के अनुरूप है। गुरुग्राम स्थित हिंद महासागर क्षेत्र सूचना संकलन केंद्र :आईएफसी.आईओआरडब्लू समुद्री सूचना के आदान.प्रदान का केंद्र बन गया है जिसमें कई देशों ने अपने संपर्क अधिकारी तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना ने भारीदार देशों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने के साथ. साथ जल दस्तीयुत रोधी अभियानों को तेज किया है। समुद्री प्रदूषण नियंत्रण एक नया विषय है जिसके तहत भारत ने श्रीलंका और मॉरीशस के सहायता अनुरोधों पर कार्रवाई की है। जैसाकि सोमवार को हुई यूएनएससी बैठक में अनेक वक्ताओं ने कहा है एक आझूति विषय पर परिषद में चर्चा करवाना एक उल्लेखनीय सफलता है। परिषद में समुद्री सुरक्षा पर चर्चा करवाने के विगत प्रयासों विशेष रूप से पी.5 सदस्यों की अवधारणा में मतभेद के कारण सफल नहीं रहे थे। सोमवार की बहस में बाधाएं स्पष्ट रूप से सामने आई। फिर भी ए परिषद ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष के वक्तव्य के रूप में एक परिणामी दस्तावेज को पारित किया। भारत की वैशिक प्रतिष्ठा और इसकी रचनात्मक भूमिका ने यह साबित कर दिया है कि आपसी चर्चा से वैशिक मुद्दों पर वास्तव में प्रगति की जा सकती है। भारत ने इस खुली बहस की सफलतापूर्वक अध्यक्षता करके विश्व मंच पर एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी साथ कायम की है। हमारे अध्यक्ष पद के पहले अभिभाषण कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम ने हमारे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले सुरक्षा परिषद तथा एक स्थायी सदस्य के रूप में प्रसिद्ध छाँसूची टेबलपृष्ठ पर भारत के सही स्थान पाने के साथ असंख्य वैशिक चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

पंचायती राज

इतजार करना पड़ता है। कोइ काम तेजो से नहीं हो पाता है। भारत में लगभग 5000 सांसद और विधायक के अलावा 28 लाख ग्रामीण प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन सत्ता की विकेंद्रीकरण की यह कोशिश कितनी सफल हुई है। धनबल और बाहुबल के कारण स्थानीय जगहों पर सांसदों और मंत्रियों का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव लड़ना भी पैसों के खेल हो गया है जो कि गरीब और वंचित लोगों के बूते से बाहर हो गया है। ग्राम पंचायत हमेशा से ही सांसदों और विधायकों पर निर्भर रहता है। इस से गांवों में स्वराज का सपना परा नहीं हो पा रहा है।

पचायता राज में अमा भा बहुत कुछ ठाक करने का आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में शिक्षा की जागरूकता राजनीति के प्रति जागरूकता और अधिकारों को समझाए पंचायतों को राजनीति का आँखड़ा नहीं बनने देनाए पंचायत के चुनाव में सियासी दलों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधाए पंचायत के फंडों पर निगरानी और प्रतिनिधि और पदाधिकारी के घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर ध्यान और पंचायत राज को लोकतांत्रिक रूप से मजबूत करने के लिए पंचायतों को अपनी योजना खुद तैयार करना और उसे लागू करने का अधिकार देना चाहिए और प्रतिनिधि को आत्मनिर्भर निर्भर बनाना चाहिए और समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए। तब जाकर महात्मा गांधी का पूर्णतः स्वराज वाला सपना साकार हो पाएगा।

राजनीति में दाग अच्छे हैं

प्रभुनाथ शुक्ल

राजनीति में सुचिता का सवाल सबसे अहम मसला है। बेदाग छिवि के राजनेता और चरित्र की राजनीति वर्तमान दौर में हासिए पर है। टीवी का वह विज्ञापन भारतीय राजनीति पर सटीक ढैठता है कि घ्यांग अच्छे हैं। देश में यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा है कि राजनीति का अपराधीकरण क्यों हो रहा है। दागदार और आपराधिक वृत्ति के व्यक्तियों को राजनीतिक दल प्रश्रय क्यों दे रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है या फिर राजनीति ही अपराधियों द्वारा बाहुलियों के हैं। जहाँ अब बेदाग चेहरों का कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि एक चरित्रवान व्यक्ति राजनीति की बदबू से खुद को अलग रखना चाहता है। राजनीति में अब जनसेवा की आड़ में जेब सेवा हो रही है। पहले जैसी साफ़ सुधरी राजनीति की उम्मीद करना बैडमानी है। कल जिन अपराधियों का सहारा लेकर लोग राजनेता बनते थे आज वही अपराधी खुद को सुरक्षित रखने के लिए राजनेता बन गया है। यह बदलती भारतीय राजनीति का नया चेहरा है। लेकिन उम्मीद बाकि है। सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व में दिए गए अपने फैसले के अवमाना मामले में हाल में एक अहम फैसला सुनाया है। जिससे यह उम्मीद जगी है कि राजनीति में थोड़ी सुचिता आ सकती है। लेकिन अभी अदालत को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत कुछ करना है। लोगों कि रही सही उम्मीद बस अदालत पर है। सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद राजनीति कितनी पवित्र होगी यह तो वक़्त बताएगा। लेकिन देश और समाज के साथ प्रबुद्ध वर्ग में एक संदेश यह गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिहार चुनाव से पूर्व एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि आपराधिक छिवि के उम्मीदवारों का व्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। इसकी सूचना अखबारों आनी नहीं होती। जो भी देश के लोगों को इसकी विविधता देता है, वो उसे

चाहिए। जनता को भी यह मालूम होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वह चुनने जा रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। उसकी सामाजिक छवि क्या रही है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उर्द्धी याचिकाओं कि अवमनना की सुनवाई करते हुए अदालत सख्तरुख अपनाया है। इस गुनाह के लिए भाजपाए कांग्रेसए माकपाए राकांपा समेत आठ दलों पर पांच से एक लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा बिहार विधानसभा में चुनकर गए आपराधिक नेताओं की सूची सार्वजनिक करने के साथ राजनीतिक दलों को यह भी बताने को कहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उहोंने आपराधिक छवि वालों को पार्टी से उम्मीदवार बनाया। क्या पूरे बिहार में चरित्रवान यानी बेदाग छवि का उम्मीदवार मिला ही नहीं घृणित रूप से सर्वीच्छ अदालत का फैसला स्वागत योग्य है। सर्वीच्छ अदालत के फैसले पर अगर चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम करता है तो देश में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत होगी। अदालत ने अपराधियों के बारे में खूब प्रचार, प्रसार कर जनता को जागरूक करने को कहा है। इसके लिए मिडिया और अन्य संदेश माध्यमों का भी सहारा लेने की बात कही है। अदालत ने राजनीति के अपराधी करण पर गहरी चिंता भी जाताई है। चिंता जताना लाजमी भी है क्योंकि राजनीति में अब एक आदमी चाहकर भी प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके पास न बाहुबल है और न धनबल। अब सत्ता और सरकारों को लोकतंत्र की पवित्रा और सूचिता से कोई सरोकार नहीं है। सत्ता और सियासत का अब सिर्फ एक ही मकशद रह गया है कि चुनावों में सामाए दामए दंडेभय और भेद के जरिए अधिक सीट निकाल कर सत्ता हासिल कि जाय। जिसकी वजह से राजनीति में अपराधियों का प्रवेश हो रहा है। क्योंकि एक बेदाग छवि का व्यक्ति यह सब नहीं कर सकता है। तभी तो राजनीति को द्वाग अछे हैं वाले व्यक्ति पसंद हैं। भारतीय संसद कि शोभा बढ़ाने वाले चालू सत्र में यानी 2019 में चुनकर आए 43 फीसदी माननीय दागी छवि के हैं। जबकि 2004 में यह 24 फीसदी था। लगातार आपराधिक पृष्ठभूमि से लाग संसद पहुंच रहे हैं। 2009 में यह 30 फीसद हो गया जबकि 2014 में यह सच्चा 34 फीसदी तक पहुंच गई।

